

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 439]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 8 अगस्त 2017—श्रावण 17, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त, 2017

आदेश

क्र. एफ बी-04-07-2017-2-पांच.— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह निदेश देती है कि वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, सतना द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के चतुर्थ तिमाही के दौरान जारी की गई बीमा पॉलिसियों पर, उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क समेकित किया जा सकेगा तथा उसका भुगतान मध्यप्रदेश में किसी भी शासकीय कोषालय में निम्नलिखित शर्तों पर किया जा सकेगा:—

1. ऐसी प्रत्येक पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा यह उपदर्शित किया जाएगा कि उस पर देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान उपर्युक्त रीति से कर दिया गया है. ऐसे पृष्ठांकन केवल इस आदेश के अधीन भुगतान की गई समेकित स्टाम्प शुल्क की रकम की सीमा तक किए जा सकेंगे.
2. समेकित रकम रुपए 33.00 लाख (तैंतीस लाख रुपए) मात्र के भुगतान के चालान की एक प्रति मध्यप्रदेश के किसी शासकीय कोषालय में चतुर्थ तिमाही के लिए उप-महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय, जबलपुर में प्रस्तुत की जाएगी.
3. उस अवधि को जिसके लिए शुल्क का समेकन किया गया है समाप्त होने के तत्काल पश्चात्, बीमित राशि की पॉलिसी क्रमांक तथा चतुर्थ तिमाही के अंत में पॉलिसियों पर भुगतान किए गए शुल्क की सही रकम से मिलकर बनने वाली विवरणी उप-महानिरीक्षक पंजीयन, जबलपुर के कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2017

क्र. एफ बी-04-07-2017-2-पांच.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-04-07-2017-2-पांच (29), दिनांक 8 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 8th August 2017

ORDER

No. B-4-07-2017-2-V-(29).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), the State Government, hereby, directs that the stamp duty chargeable under the said Act on insurance policies issued by Senior Divisional Manager, Life Insurance Corporation of India, Satna during the four quarter of financial year 2017-18 may be consolidated and paid into any Government Treasury in Madhya Pradesh on the following conditions:—

1. It shall be indicated by endorsement on each policy of insurance that the stamp duty payable thereon has been paid in the aforesaid manner. Such endorsement would be made only to the extent of consolidated stamp duty amount paid under this order.
2. A copy of the challan of payment of consolidation amount of Rs. 33.00 Lakh (Rupees Thirty three Lakh) only in any Government Treasury of Madhya Pradesh for four quarter shall be submitted in the office of Deputy Inspector General of Registration, Jabalpur.
3. Immediately after the end of the period for which consolidation of duty has been made, the statement consisting of the policy numbers of sum insured and the exact amount of stamp duty paid on the policies at the end of Four quarter shall be submitted to the office of Deputy Inspector General of Registration, Jabalpur.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.